ग्रामीण विकास व भू-संसाधन राज्यमंत्री रामकृपाल यादव का रांची जिले के अनगड़ा क्षेत्र का दौरा

गांवों के विकास से ही बदलेगी देश की सूरत

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं धरातल पर पहुंचे और ग्रामीणों का समुचित लाभ हो. इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामीण विकास एवं भू-संसाधन विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने रांची जिले के अनगड़ा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान खेती-किसानी से जुड़े किसानों से उसकी स्थिति जानने की कोशिश की, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण किस तरह से उठा रहे हैं, यह भी जानने की कोशिश की. टपक व गुरुत्व सिंचाई योजना समेत महिला सखी मंडलों से भी मुखातिब हुए. सभी ने क्षेत्र में पानी की समस्या को केंद्रीय राज्यमंत्री के सामने रखा. मंत्री ने गांवों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहरायी. करीब चार घंटे अनगड़ा क्षेत्र में बीताने के दौरान कई चीजों को बारिकी से केंद्रीय राज्यमंत्री ने देखा. ग्रामीणों में और बेहतर करने की ललक पैदा करने संबंधी कई निर्देश अधिकारियों को दिये. पढ़िए समीर रंजन का यह आलेख.

किसान गोवर्द्धन मुंडा के खेत में लगे फसलों को देखते केंद्रीय मंत्री व अधिकारीगण.

रांची जिले का अनगड़ा प्रखंड. अनगड़ा की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारे, जो यह बताने के लिए काफी था कि अन्य दिनों की भांति 17 फरवरी का दिन यहां के लोगों के लिए कुछ खास था. खास इस मायने में, क्योंकि ग्रामीण विकास एवं भू-संसाधन विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री रामकृपाल यादव अनगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों को केंद्रीय मंत्री ने बारिकी से देखने व समझने की कोशिश की. केंद्रीय राज्यमंत्री रामकृपाल यादव का काफिला सबसे पहले पहुंचता है अनगड़ा प्रखंड के जानुम गांव में. जानुम गांव के एक किसान गोवर्द्धन मुंडा से खेती-किसानी के साथ सरकारी सहयोग संबंधी विस्तार से जानकारी प्राप्त की.

गोवर्द्धन मुंडा का 25 डिसमिल से तीन एकड़ का सफर

टपक सिंचाई के माध्यम से जानुम गांव के किसान गोवर्द्धन मुंडा की कामयाबी के सभी कायल हैं. वर्ष 2010 में 25 डिसमिल से शुरू हुआ खेती अब तीन एकड़ में फैल गया है. किसान गोवर्द्धन मुंडा कहते हैं, शुरुआती दिनों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के हालिद और शांति दीदी के माध्यम से पता चला कि बूंद-बूंद सिंचाई से भी खेती होती है. हालांकि उस वक्त कुछ कर नहीं रहा था, तो कुछ करने को सोचा और इस काम में जेएसएलपीएस का सहयोग मिला. रांची के एक अन्य क्षेत्र में इस योजना को सामने से देखने और समझने को मिला. इसे देख खुद भी टपक सिंचाई के माध्यम से खेती करने का ठानी. टपक सिंचाई से खेती करने के लिए चयनित होने के बाद जेएसएलपीएस की ओर से एक साल का प्रशिक्षण मिला, वहीं सिंचाई के लिए टंकी और पाइप मुहैया कराया गया. शुरुआती दिनों में टमाटर लगाया और करीब 30 हजार रुपये की आमदनी हुई. इसके बाद गोभी और खीरा भी लगाया और इसमें भी आमदनी अच्छी हुई. गोवर्द्धन कहते हैं कि आमदनी ठीक होने के कारण धीरे-धीरे खेतों का भी विस्तार किया और आज तीन एकड़ पर टपक सिंचाई योजना के माध्यम से खेती कर रहे हैं. वर्तमान में लहसून, प्याज और मटर लगाया गया है. इसके अलावा ब्रोकली, खरबूजा, सेम का भी उत्पादन कर रहे हैं. मटर का समय अब खत्म होने के संबंध में गोवर्द्धन कहते हैं कि अब इसकी कीमत अच्छी मिलेगी, इसी कारण हर साल मटर का उत्पादन ऑफ सीजन में किया जाता है. वर्तमान में करीब तीन लाख रुपये की आमदनी साल में हो जा रही है. कहते हैं, अब खुशी इस बात की भी होती है कि पहले दूसरों के खेतों में खुद मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब सात-आठ मजदूरों को खुद अपने खेतों में काम करवा कर रोजगार दे रहे हैं. एक विशेषज्ञ की भांति गोवर्द्धन कहते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की काफी समस्या है और ऐसी स्थिति में टपक सिंचाई योजना यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है. इससे उतनी ही पानी पेड़ों में दी जाती है, जितना उसे जरूरत हो. इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती है. इतना ही नहीं, पानी के अलावे पेड़ों में दिये जानेवाले रसायन भी पाइप के माध्यम से ही दिया जाता है. गोवर्द्धन का एक छोटा-सा पॉली हाउस भी है. इसमें उन पौधों को तैयार किया जाता है, जिसे वो अपने खेतों में लगाते हैं. जैविक खाद का भी खुद ही निर्माण करते हैं. इसके लिए बकायदा एक अलग स्थान में जैविक खाद को तैयार भी किया जाता है. गोवर्द्धन अब अपने खेतों को और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं.

समूह से जुड़ कर महिलाओं में आया आमूल-चूल परिवर्तन

जानुम गांव में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह भी काफी सक्रिय है. सरईफुल स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुष्मिता देवी कहती है कि समूह से जुड़ने के बाद खुद और गांव में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. वर्ष 2013 में समूह से जुड़ी सुष्मिता कहती है कि महिलाओं में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है. वर्तमान में सीनियर सीआरपी के तौर पर काम कर रही सुष्मिता ग्राम संगठन के गठन के लिए अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित भी कर रही है. कहती हैं, सिल्ली क्षेत्र में ग्राम संगठनों का विस्तार किया जा रहा है. आजीविका कृषि मित्र के तौर पर काम कर रही पंपावती देवी कहती है कि जानुम गांव में करीब आठ स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है. हालांकि उपस्थित एसएचजी दीदियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री रामकृपाल यादव से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द समाधान की मांग की है.

गुरुत्व सिंचाई योजना का जायजा लेने तिरलाकोचा गांव पहुंचे मंत्री

जानुम गांव में खेती-किसानी से जुड़े किसान और एसएचजी महिलाओं से मिल कर केंद्रीय मंत्री का काफिला पहुंचा राजाडेरा पंचायत के तिरलाकोचा गांव. इस गांव में रामकृष्ण मिशन के सहयोग से गुरुत्व सिंचाई योजना के तहत खेतों में पानी पहुंचायी जा रही है. गुरुत्व सिंचाई योजना से होनेवाले लाभ के बारे में जानने की कोशिश केंद्रीय राज्यमंत्री ने की. इस गांव में नशा और मांसाहार पूरी तरह से प्रतिबंधित है. यह सुन केंद्रीय मंत्री ने तिरलाकोचा के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गये, जहां बच्चों के लिए भोजन बन रहा था. केंद्रीय मंत्री ने एमडीएम में कार्यरत एक महिला से खाने की मैन्यू के बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा शाकाहारी खाना बना कर बच्चों को देने की बात कही. गांव के लोग कहते हैं कि पहाड़ के किनारे बसे होने के बावजूद नशा और मांसाहार से ग्रामीण कोसो दूर हैं.

कैसे बदली गांव की तस्वीर

तिरलाकोचा गांव के पहाड़ों में एक ऐसे स्त्रोत की पहचान की गयी, जहां से वर्षाजल तेज गति से बहता है. फिर वहां चेकडैम बनाकर पानी के बहाव को रोका गया. इसके बाद पानी को गांव तक लाने के लिए रास्ते को चिह्नित करते हुए अलग-अलग संचयन टैंक बनाये गये. फिर हाई डेंसिटी इंजीनियरिंग पाइपों के सहारे पानी को गांवों में लाया गया और फिर डिस्ट्रीब्यूटर टैंकों का निर्माण कर पानी गांवों और खेतों में पहुंचाया गया. सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद अब गांव के लोग एक फसल की जगह कई फसल उपजाने लगे हैं. आज लोग खरीफ के अलावा सब्जियों की खेती भरपूर मात्रा में करते हैं. अनुसूचित जाति के इस गांव में लगभग 28 परिवार रहते हैं जो पूरी तरह खेती पर निर्भर ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी है. गांव के लोग कहते हैं कि वे सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं जो गुरुत्व सिंचाई के माध्यम से ही संभव हो पाया है. पानी की उपलब्धता सालों भर रहती है जिससे खेती में दिक्कतें नहीं आती है.

लाह खेती से जुड़े हैं गांव के किसान : चंद्रमोहन बेदिया

गांव का एक सफल किसान है चंद्रमोहन बेदिया. इंटरमिडिएट की पढ़ाई के बाद चंद्रमोहन पूरी तरह खेती में ही रम गया और आज एक सफल किसान है. धान के अलावा अदरख, टमाटर, मिर्ची, ओल सहित लाह की उन्नत खेती कर प्रति वर्ष दो से ढाई लाख रुपये कमा रहा है. चंद्रमोहन कहते हैं कि अगर सही से समय पर दवा का छिड़काव किया जाए, तो एक पेड़ से 10 क्विंटल तक लाह प्राप्त किया जा सकता है. चंद्रमोहन ने करीब 40 से ज्यादा पेड़ों पर लाह की खेती कर रहे हैं. गांव के लगभग 28 में से 25 परिवार लाह की खेती से जुड़े हैं और इसकी अच्छी उपज हो रही है. लेकिन, समस्या यह कि अगर हमें लाह को खुदरा में बेचना पड़े तो काफी कम कीमत मिलती है. चंद्रमोहन ने 'राजाडेरा युवा किसान प्राकृतिक लाख उत्पाद सहयोग समिति' का गठन किया है, जहां सभी किसान एक जगह लाह को इक्कट्ठा करते हैं और फिर उसे बड़े बाजार में बेचते हैं, जिससे लाह की अच्छी कीमत मिल जाती है. इसी गांव के एक अन्य किसान हैं नारायण बेदिया. जिन्हें वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लाह उत्पादक के पुरस्कार से नवाजे हैं. किसानी से नारायण सलाना लगभग पांच लाख रुपये कमा लेता है.

पहाड़ से गिरते पानी को संजोने का विशेष तरीका गुरुत्व सिंचाई योजना : सुभाष कुमार, जल विशेषज्ञ

गुरुत्व सिंचाई योजना के बारे में रामकृष्ण मिशन के सुभाष कुमार ने बताया कि पहाड़ से गिरते पानी को बचाने और उससे खेती करने की पद्धति के तहत इस योजना की शुरुआत हुई. इसके तहत पहाड़ से गिरते पानी को सबसे पहले एक बड़े से टंकी में जमा किया जाता है. फिर गुरुत्व विधि के माध्यम से खेत और घरों में पानी पहुंचाया जाता है.

सखी मंडल की सदस्यों से मुखातिब हुए केंद्रीय मंत्री

मंत्री और अधिकारियों को अगला पड़ाव था गेतलसूद पंचायत सचिवालय. यहां पहुंच कर मंत्री ने काफी संख्या में पहुंची सखी मंडलों से मुखातिब हुए और आजीविका मिशन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली. महिला समितियों के इन क्रियाकलापों से मंत्री समेत अधिकारी काफी प्रभावित हुए. इस दौरान सखी मंडलों के बीच बैंकों ने ऋण वितरण किया गया. इसके तहत एक लाख 90 हजार रुपये का ऋण ज्योति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मिला, वहीं रेशमपदा गांव के चंपा महिला समूह और सालहन की निशा महिला सूमह की दीदियों को 50-50 रुपये का ऋण दिया गया. इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मोहनी देवी, झालो देवी, जलेश्वर महतो व कमल महतो को स्वीकृति पत्र मिला.

दीदियों को प्राथमिकता देना गर्व की बात : स्वर्णिमा देवी

मसनिया ग्राम संगठन की स्वर्णिमा देवी कहती हैं, जेएसएलपीएस के माध्यम से गांवों में दीदियों ने काफी काम किये हैं. कहती है, अनगड़ा प्रखंड में लक्षित दीदियों की संख्या 17,900 है, जिसमें 16,850 दीदियां विभिन्न संगठनों से जुड़ चुकी है. विभाग की ओर मिली राशियों से दीदियों ने कई कामों को अंजाम दिये हैं. सरकार की ओर से दीदियों को प्राथमिकता देना गर्व की बात है.

पशु मृत्यु दर में आयी कमी : अहिल्या देवी

आजीविका पशु सखी अहिल्या देवी ने पशुओं की देखभाल संबंधी विस्तार से जानकारी दी. कहती हैं, पहले पुरुष वर्ग काफी सशंकित नजरों से देखते थे. पशु दीदियों के काम को देखते हुए धीरे-धीरे उनमें बदलाव आया. जेएसएलपीएस ने बखूबी किया. गांवों में बकरियों की मृत्यु दर जहां पहले काफी थी, वहीं पशु सखियों की उचित देखभाल से मृत्यु दर में काफी कमी आयी है.

बहुआयामी कार्य कर रहे हैं यहां के सखी मंडल : एनएन सिन्हा

यहां का ग्राम संगठन और सखी मंडल काफी सुदृढ़ है. सखी मंडल बहुआयामी कार्य कर रही है, चाहे कृषि, पशुपालन, वनोउपज, सिंचाई आदि के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में यहां की दीदियों का भरपूर समर्थन मिलता है. गांवों के विकास के प्रति सरकार काफी चिंतित है और इसी दिशा में सरकार और अधिकारी प्रयासरत हैं. किसानों के खेत में पानी मिले, इसी उद्देश्य से जल संचय संबंधी डोभा निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

टोलों पर भी ग्रामीण विकास विभाग की नजर : नीलकंठ सिंह मुंडा

गांव ही नहीं वरन हर टोले में भी ग्रामीण विकास की योजनाएं धरातल पर उतरने लगा है. हर गांवों में डोभा निर्माण में तेजी आयी है. अब मनरेगा से जुड़े मजदूरों का भुगतान बैंकों के माध्यम से 48 घंटे में होगा. पहले स्वयं सहायता समूह की संख्या करीब 52 हजार थी, जो अब बढ़ कर 65 हजार के करीब पहुंच चुका है. इस वर्ष 80 हजार महिला समूह के गठन का लक्ष्य निर्धारित किये हैं.

जन-जन तक पहुंचे विकास की किरण : रामकृपाल

राज्य में ग्रामीण विकास का कार्य संतोषजनक है. योजनाओं के सफल संचालन के लिए कभी राशि रूकावट नहीं बनेगा. केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग की राशि में 25 प्रतिशत का इजाफा किया है. जन-जन तक विकास की किरणें पहुंचे, गांवों में खुशहाली आये और पलायन रोकना ही विभाग का मुख्य उद्देश्य है. खेती-किसानी और सखी मंडल के कार्यों को देख आजीविका मिशन का सही स्वरूप देखने को मिल रहा है.